



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2010/श्रावण 4, 1932

No. 206]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2010/SHRAVANA 4, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2010

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कुछेक रबड़ रसायनों (एमबीटीएस) पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

**फा. सं. 15/9/2010-डीजीएडी.**—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कुछेक रबड़ रसायनों (एमबीटीएस) (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी के अंतिम जाँच परिणाम संबंधी अधिसूचना दिनांक 6-7-2005 की अधिसूचना सं. 14/09/2004-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। जाँच परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 27-09-2005 की अधिसूचना सं. 87/2005-सी.शु. के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

## 2. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

यतः सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार यदि पाटनरोधी शुल्क पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी सं. 2006 का 16893 में यह माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जाँच करने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

### 3. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त एक विशिष्ट रबड़ रसायन अर्थात् एमबीटीएस है। “एमबीटीएस” का विनिर्माण उचित ऑक्सीकरण एजेंटों का उपयोग करते हुए एमबीटी के सोडियम लवण के ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। इन उत्पादों का उपयोग अन्य के साथ-साथ मुख्यतः ऑटोमोटीव टायर, ट्यूब उद्योग तथा कन्वेयर बेल्टिंग एवं फुटवियर उद्योग में भी किया जाता है। विभिन्न अन्य उपयोगों में प्रयुक्त रबड़ के अन्य रसायन विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं। प्राधिकारी ने पूर्व में यह निर्धारित किया था कि संबद्ध वस्तु का कोई अनन्य आईटीसी एचएस वर्गीकरण नहीं है और विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न सीमाशुल्क उपशीर्षों के अंतर्गत किया गया है जिनमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 38.12.10, 38.12.20 तथा 38.12.30, 29.34.20 एवं 29.25.20 (6-अंकीय स्तर) शामिल हैं। उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और संबद्ध जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

### 4. शामिल देश

वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य (जिसे चीन जन. गण. भी कहा गया है) है।

### 5. जाँच की अवधि

वर्तमान निर्णायक समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 (12 माह) की है। तथापि, क्षति विश्लेषण की अवधि में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और जाँच अवधि शामिल होगी।

### 4. प्रक्रिया

I) दिनांक 6 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. 14/9/2004-डीजीएडी के तहत जारी अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 27 सितम्बर, 2005 की सी.शु. अधिसूचना सं. 87/2005 द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, लागू शुल्क का सतत रूप से बनाए रखने की जरूरत की समीक्षा जाँच शुरू करते हैं। इस समीक्षा में 6 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. 14/9/2004-डीजीएडी (मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं।

### II) सूचना प्रस्तुत करना

घरेलू उद्योग द्वारा शुल्क जारी रखने की आवश्यकता का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर निर्धारित प्रपत्र (घरेलू उद्योग हेतु

आवेदन) में इस आशय से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि पहले से लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।

संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत स्थित उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
कमरा सं. 243  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकारों हेतु उसका एक अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

### III) समय सीमा

घरेलू उद्योग से सूचना प्रस्तुत होने पर, सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनके पते उपलब्ध हैं, को इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को लिखित में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की सलाह एक पत्र के जरिए दी जाएगी। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिनके पते उपलब्ध न हों, भी इस अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रयोजनार्थ आवेदन के अगोपनीय रूपांतर को सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

### IV) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2010

**(Sunset Review)**

**Subject :— Initiation of Sunset review of anti-dumping duty imposed against Certain Rubber Chemicals (MBTS) originating in or exported from China PR.**

**F. No. 15/9/2010-DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Certain Rubber Chemicals (MBTS) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country). The final findings notification of the Authority was published vide notification No 14/9/2004-DGAD dated 6th July 2005. On the basis of the findings, definitive anti dumping duties on the subject goods imported from the subject country were imposed by the Central Government vide notification No. 87/2005 Customs dated 27.09.2005.

**2. Initiation of Sunset Review**

WHEREAS in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard, Hon'ble Delhi High Court in WP No 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory. Therefore, pursuant to the above orders of the Hon'ble High Court, the Designated Authority hereby initiates sunset review in accordance with section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

**3. Product under Consideration**

The Product under Consideration is a specific rubber chemical used in manufacture of rubber products, i.e. MBTS. 'MBTS' is manufactured by oxidation of sodium salt of MBT using suitable oxidizing agents. The products are mainly used in automotive tyres and tubes industry and also in conveyor belting and footwear industry amongst others. Other rubber chemicals used in various other uses are not covered within scope of the product under consideration.

The Authority had previously determined that there is no dedicated ITC HS Classification for the subject goods and product under consideration were imported under various subheadings of customs, which includes 38.12.10, 38.12.20 and 38.12.30, 29.34.20 and 29.25.20 (at six digit levels) of the Customs Tariff Act. The said customs classifications are only indicative and are in no way binding on the scope of the present investigation.

#### 4. Country Involved

The country involved in the present investigation is People's Republic of China (also referred to as China PR).

#### 5. Period of Investigation

The Period of Investigation (POI) for purpose of the present Sunset Review is April 1, 2009 to March 31, 2010 (12 Months). However, the period for injury analysis shall cover the years 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 & the POI.

#### 6. Procedure

I) Having decided to review the final findings issued vide Notification No. 14/9/2004 DGAD dated 6th July, 2005 and final duty imposed vide Customs Notification No. 87/2005 dated 27th September, 2005, the Authority hereby initiates investigation to review the need for continued imposition of the duties in force and to examine whether cessation of Anti Dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of Dumping and injury on imports of the subject goods originating in or exported from subject country in accordance with the Act and the AD Rules. The review covers all aspects of Notification No. 14/9/2004 DGAD dated 6th July, 2005 (final findings of the original investigation).

#### II) Submission of Information

The Domestic industry is required to submit information on prescribed pro forma (Application for Domestic industry) and information on likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury or both substantiating the need for continuation of duty within forty days (40 days) of issue of this notification.

The exporters in subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Ministry of Commerce and Industry  
Department of Commerce  
Room No. 243  
Udyog Bhavan New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

#### III) Time Limit

On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/information within 40 days from date of this notification. For this purpose non confidential version of

281250110-2

the application would be placed in the public file. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules *supra*.

**IV) Inspection of Public File:**

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. Where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHARY, Designated Authority